रेलवे वर्दी समिति

१९८९. श्री नरदेव स्नातक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों को वर्दियां देने सम्बन्धी नियमों में एकरूपता लाने के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा मई, १९५५ में जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उसने अपना काम समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब पूरा हुआ और उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(घ) कितनी सिफारिशों पर कार्यवाही की जा चुकी है और कितना सिफारिशों पर कार्यवाही होना बाकी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) कमेटी ने १०-८-१९५७ को अपनी रिपोर्ट दी । इस कमेटी में हर रेलवे के स्टोर्स विभाग का एक-एक सीनियर अफसर और रेलवे बोर्ड के ३ अफसर थे ।

(ग) कमेटी की मुख्य सिफारिश नीचे लिखी बातों के बारे में हैं :—

(१) किन-किन कर्मचारियों को वर्दी मिलनी चाहिये इसमें सम्बन्धित सिद्धान्त ;

(२) वर्दियां किस हिसाब से दी जायें ;

(३) वर्दियों का रंग और उनकी बनावट कैसी हो, और

(४) वर्दियां कैसी तैयार कराई जायें ।

(घ) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

रेलों में भ्रष्टाचार के मामले

१९९०. श्री नरदेव स्नातक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने के कारण अब तक कितने रेलवे पदाधिकारियों को नौकरी से अलग किया जा चुका है ;

(ख) उनमें से कितने ट्रैफिक, इंजीनियरिंग, पर्मनल, चिकित्सा तथा भाण्डार सम्बन्धी विभागों से सम्बन्धित थे और वे किस किस रेलवे के थे ; और

(ग) चिकित्सा सम्बन्धी विभाग के कितने पदाधिकारियों के मामले चिकित्सा परिषद् को भेजे गये ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) . (क) १९५७ में अब तक चार का ।

(ख) एक अफसर मध्य रेलवे के स्टोर्स विभाग का था और बाकी तीन पश्चिम रेलवे के थे . एक सिविल इंजिनियरिंग, एक मेकैनिकल इंजिनियरिंग और एक लेखा विभाग का ।

(ग) कोई नहीं ।

Passenger Amenities

1991. Shri Yajnik: Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) the terms and conditions on which a monopoly is given to various persons to run the hair cutting and shaving saloons on the Western Railway stations;

(b) whether Government are aware that the licensees employ other people as their sub-agents to run these establishments on very unjust terms and that the sub-agents get a very miserable share of their earnings, and

(c) whether Government would take any action to see that all establishments are run personally by those who are given the licenses by the Railway Ministry?